



**RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LIMITED**  
 Corporate Identity Number (CIN)-U40102RJ2000SGC016484  
 Regd. Office: Vidyut Bhawan, Janpath, Jaipur-302005  
 Ph.No.0141-2740413; Fax No.:0141-2740759  
 E-mail: rvun\_control@yahoo.com; website: www.rvunl.com

No.RVUN/CCOA(HQ)/Control/F. /D. 639

Dated : 18-7-17

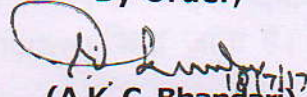
**ORDER**

The Chairman and Managing Director in consultation with the Director (Finance), RVUN is pleased to adopt the State Government's Order No. प. 8(10)वित्त/नियम/2009, जयपुर dated 14.06.2017 issued by the Finance Department, GoR (Copy enclosed), wherein, pursuant to decision made by the Hon'ble High Court in PIL No. DBCWP 20183/2013, the Finance Department, GoR has withdrawn its earlier order dt. 30.01.2017 which was adopted by RVUN vide order No. 2290 dt. 08.03.2017.

Accordingly, whose HRA was stopped/ disallowed, pursuant to aforesaid order the payment of arrear of HRA shall be allowed to them as per provisions of House Rent Allowance Rules, 1989.

**Encl: As Above**

**By Order,**

  
 (A.K. C. Bhandari)

**Chief Controller of Accounts (HQ)**

Copy submitted/ forwarded to the following for information and immediate compliance:

1. The Chief Engineer/Addl. C.E./Dy. C. E.( ), RVUN, \_\_\_\_\_.
2. The Chief Controller of Accounts (KSTPS), RVUN, Kota.
3. The Chief Accounts Officer ( ), RVUN \_\_\_\_\_.
4. The Joint Director ( )/ Company Secretary, RVUN, \_\_\_\_\_.
5. The Superintending Engineer ( ), RVUN \_\_\_\_\_.
6. The Dy.COA/ Sr. Accounts Officer ( ), RVUN, \_\_\_\_\_.
7. The Accounts officer ( ), RVUN \_\_\_\_\_.
8. The Assistant Accounts Officer ( ), RVUN.
9. PS to CMD, RVUN, Jaipur.
10. PA to Director ( ), RVUN, Jaipur.

  
 Chief Controller of Accounts (HQ)

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
नियम अनुभान

प.8(10)वित्त/नियम/2009


जयपुर, दिनांक : 14.06.2017

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या DBCWP 20183/2013 योगेश शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 05.12.2016 की अनुपालना में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.01.2017 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे कि राजकीय सेवा में सेवारत पति-पत्नी जो एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित हैं तथा एक ही मकान में रहते हों तो, उनमें से एक का ही मकान किराया भत्ता, जो दोनों में जिसका अधिक हो, आहरित किया जावे। यह आदेश माह जनवरी 2017 के वेतन से प्रभावी किया गया था।

उपरोक्त संदर्भित जनहित याचिका संख्या DBCWP 20183/2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2017 की पालना में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.01.2017 को प्रत्याहारित (withdraw) किया जाता है।

आदेश दिनांक 30.01.2017 की पालना में जिन राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता का भुगतान माह जनवरी 2017 से रोका गया है, का एरियर मकान किराया भत्ता नियम, 1989 के प्रावधानानुसार देय होगा।

  
(अनिल राजपाल)  
शासन सचिव, वित्त (बजट)